

1. मोदी सरकार के 11 वर्ष: 11 महायोजनाएं जिन्होंने बदला आम भा

बीते 11 वर्षों के कार्यकाल में मोदी सरकार का मुख्य फोकस सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर रहा है। सरकार ने शासन के पारंपरिक तरीकों को बदलते हुए सीधे लाभार्थियों के खातों में लाभ पहुंचाना (DBT) सुनिश्चित किया है। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और योजनाओं की पहुंच शत-प्रतिशत नागरिकों तक संभव हो पाई है।

आम आदमी के जीवन में आया युगांतरकारी बदलाव

इन 11 महायोजनाओं ने न केवल लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है, बल्कि उन्हें एक गरिमामय जीवन भी प्रदान किया है। बुनियादी ढांचा हो, सामाजिक सुरक्षा हो या फिर डिजिटल बैंकिंग, हर क्षेत्र में आम नागरिकों को सीधा लाभ मिला है। इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों परिवारों के जीवन में बड़ा और स्थाई सकारात्मक बदलाव आया है।

2. वित्तीय समावेशन की बड़ी क्रांति: पीएम जनधन योजना से बैंकि

देश के हर नागरिक को बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से 28 अगस्त 2014 को पीएम जनधन योजना (PMJDY) का ऐतिहासिक शंखनाद किया गया था। यह योजना वैश्विक स्तर पर वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी पहलों में से एक मानी जाती है, जिसने बैंकिंग की परिभाषा को पूरी तरह बदल दिया।

जनधन खाते की प्रमुख विशेषताएं और लाभ

- >> शून्य बैलेंस खाता: इस योजना के अंतर्गत किसी भी न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती है।
- >> रुपये डेबिट कार्ड: सभी खाताधारकों को मुफ्त में स्वदेशी रुपये डेबिट कार्ड जारी किया जाता है।
- >> ओवरड्राफ्ट सुविधा: खाताधारकों को पात्रता के आधार पर 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट वित्तीय सहायता मिलती है।
- >> विशाल लाभार्थी आधार: सरकारी डेटा के अनुसार, अब तक देश भर में रिकॉर्ड 56.38 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं।

3. हर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा का कवच: सुरक्षा बीमा, जीवन ज्य

असंगठित क्षेत्र के कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भविष्य की चिंताओं से मुक्त करने के लिए मोदी सरकार ने 9 मई 2015

को सामाजिक सुरक्षा की तीन बड़ी योजनाओं की शुरुआत की थी। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को बेहद कम प्रीमियम पर जीवन और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है।

पीएम सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति योजना

पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के नागरिकों को मात्र कुछ रुपए के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। आंशिक वकिलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए का कवर मिलता है। वहीं, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 18 to 50 वर्ष के नागरिकों को किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्राप्त होता है। लाभार्थी आसानी से बैंक शाखा में जाकर अपना status check कर सकते हैं।

अटल पेंशन योजना (APY) से सुरक्षा बुढ़ापा

देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बुढ़ापे में नियमित आय सुनिश्चित करने के लिए अटल पेंशन योजना वरदान साबित हुई है। इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है। योजना में नियमित योगदान देने के बाद, 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए प्रतिमाह की निश्चित पेंशन आजीवन मिलती है।

4. बुनियादी जरूरतों पर बड़ा फोकस: पीएम आवास योजना से पक्का म

गरीब और बेघर परिवारों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए केंद्र सरकार ने बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। इसके तहत रहने के लिए पक्की छत और महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने का काम युद्ध स्तर पर किया गया है।

पीएम आवास योजना: 2029 तक बड़ा दायरा

हर गरीब का अपना पक्का घर होने का सपना पूरा करने के लिए 25 जून 2015 को पीएम आवास योजना (PMAY) शुरू की गई थी। इस योजना की भारी सफलता और जमीनी प्रभाव को देखते हुए सरकार ने इसके लक्ष्य का विस्तार वर्ष 2029 तक कर दिया है, ताकि छूटे हुए परिवारों को भी पक्का मकान मिल सके। आप अधिकारिक पोर्टल पर जाकर नई बने फिशर्री।।stडाउनलोड कर सकते हैं।

पीएम उज्ज्वला योजना: महिलाओं को मला धुएं से छुटकारा

देश की ग्रामीण महिलाओं को पारंपरिक चूल्हे के जहरीले धुएं और बीमारियों से बचाने के लिए 1 मई 2016 को पीएम उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन और सब्सिडी वाले सिलेंडर दिए जाते हैं। 1 जुलाई 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, पूरे भारत में 10.33 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं।

5. स्वास्थ्य और भोजन की गारंटी: आयुष्मान भारत का मुफ्त इलाज

किसी भी गरीब परिवार के लिए बीमारी का खर्च और भोजन की कमी सबसे बड़ा संकट होती है। मोदी सरकार ने इन दोनों ही मोर्चों पर ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश के करोड़ों नागरिकों को सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र प्रदान किया है।

आयुष्मान भारत योजना: स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रा

देश के वंचित परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कर्ज के जाल से बचाने हेतु 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) लागू की गई थी। इसके तहत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में दिया जाता है।

इस योजना में एक बड़ा ऐतिहासिक संशोधन 11 सितंबर 2024 को किया गया, जिसके तहत देश के सभी 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को इस मुफ्त इलाज के दायरे में शामिल कर लिया गया है, चाहे उनकी पारिवारिक आय कुछ भी हो। पात्र नागरिक इसके लिए ऑनलाइन apply online मोड में पंजीकरण कर सकते हैं।

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)

कोरोना काल के संकट के दौरान 26 मार्च 2020 को शुरू की गई यह योजना आज भी देश के गरीबों के लिए भोजन की गारंटी बनी हुई है। इस महायोजना के माध्यम से भारत सरकार देश के लगभग 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज बिल्कुल फ्री उपलब्ध करा रही है, जिससे देश में कोई भी भूखा न सोए।

6. किसानों और पारंपरिक कारीगरों को सीधा संबल: पीएम किसान सम्

भारत की आत्मा गांवों, खेतों और पारंपरिक हुनर में बसती है। देश के अन्नदाताओं और सदयियों से समाज की सेवा कर रहे शिल्पकारों को

आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए दो बेहद महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

पीएम किसान सम्मान नधि: किसानों को सीधी नकद मदद

देश के छोटे और सीमांत किसानों को खेती के खर्चों में राहत देने के लिए 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान सम्मान नधियोजनाकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता तीन बराबर कसितों (2,000-2,000 रुपए) में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। किसान अपने मोबाइल से अपनी अगली कसित का status check आसानी से कर सकते हैं।

पीएम विश्वकर्मा योजना: पारंपरिक हुनर को नई पहचान

लोहार, कुम्हार, राजमस्त्री, दर्जी और बढई जैसे 18 पारंपरिक क्षेत्रों के कारीगरों को आधुनिक तकनीक और पूंजी से जोड़ने के लिए 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजनाकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 41,188 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ अब तक 4.7 लाख से अधिक आसान और सस्ते लोन कारीगरों को बांटे जा चुके हैं।

यदि आप भी अपना खुद का नया रोजगार शुरू करना चाहते हैं और बिना गारंटी के लोन की तलाश में हैं, तो आप फ्री लोन! पीएम मुद्रा योजना से 10 लाख तक का स्वरोजगार लोन, अभी आवेदन करके वकिल्प को देख सकते हैं। इसके अलावा, बड़े उद्योगों और व्यापार के लिए बिना गारंटी 5 करोड़ तक लोन! सरकार की नई बजिनेस योजनाएंकी पूरी गाइडलाइन भी उपलब्ध है।

7. सौर ऊर्जा और मुफ्त बजिली की ओर बढ़ते कदम: पीएम सूर्यघर मु

21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और नागरिकों के बजिली बलि को शून्य करने के लक्ष्य के साथ मोदी सरकार ने ग्रीन एनर्जी पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बजिली योजना (2026 की नई पहल)

आम नागरिकों को बजिली के भारी-भरकम बलियों से हमेशा के लिए आजादी दिलाने हेतु 15 फरवरी 2024 को पीएम सूर्यघर मुफ्त बजिली योजनाकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार द्वारा भारी वित्तीय मदद दी जा रही है।

>> सब्सिडी का प्रावधान: सोलर प्लॉट स्थापित करने पर सरकार द्वारा अधिकतम 78,000 रुपए तक की बंपर सब्सिडी सीधे बैंक खाते में दी जाती है।

>> मुफ्त बजिली का लाभ: योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बजिली मिलती है।

>> अतिरिक्त आय का साधन: उत्पादित अतिरिक्त बजिली को नागरिक ग्रिड को बेचकर हर साल अच्छी कमाई भी कर सकते हैं।

>> आवेदन की प्रक्रिया: इच्छुक नागरिक राष्ट्रीय पोर्टल पर जाकर गाइडलाइंस का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे apply online कर सकते हैं।

नषिकर्ष

मोदी सरकार के बीते 11 वर्षों का यह सफर देश के आम नागरिकों के सशक्तीकरण का जीवंत दस्तावेज है। जनधन खाते से शुरू हुई वित्तीय समावेशन की यात्रा आज मुफ्त इलाज, पक्के मकान, मुफ्त राशन और मुफ्त सौर बजिली तक पहुंच चुकी है। इन 11 महायोजनाओं ने न केवल देश के गरीब और मध्यम वर्ग को आर्थिक संकटों से सुरक्षा दी है, बल्कि उन्हें देश के विकास में बराबर का भागीदार भी बनाया है। आने वाले वर्षों में इन योजनाओं का विस्तार भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने की दृष्टि में सबसे मजबूत आधार साबित होगा।

जनता के सवाल (FAQs)

पीएम जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इसके तहत नागरिकों के शून्य बैलेंस (Zero Balance) खाते खोले जाते हैं, रुपये डेबिट कार्ड मिलता है और 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है।

इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है। वहीं, आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख रुपये की सहायता राशि मिलती है। इसमें 18 से 70 वर्ष के लोग पात्र हैं।

इस योजना में 18 से 50 वर्ष तक का कोई भी नागरिक शामिल हो सकता है। योजना के अंतर्गत खाताधारक की किसी भी वजह से मृत्यु होने की स्थिति में उसके नामांकित व्यक्ति (Nominee) को 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर दिया जाता है।

अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु में नविश शुरू किया जा सकता है। इसमें 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद आपके द्वारा किए गए योगदान के आधार पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रतिमाह की नियमित पेंशन मिलती है।

देश के सभी गरीब और बेघर परिवारों को पक्का मकान मुहैया कराने के उद्देश्य से शुरू की गई पीएम आवास योजना की नरतिरता और सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसका विस्तार वर्ष 2029 तक कर दिया है।

गरीब महिलाओं को स्वच्छ ईंधन देने वाली पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 1 जुलाई 2025 तक देश भर में लगभग 10.33 करोड़ मुफ्त एलपीजी (LPG) गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिसके साथ ही सिलिंडर पर सब्सिडी भी मिलती है।

11 सितंबर 2024 को सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देश के सभी 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना में शामिल कर लिया है। अब बुजुर्गों को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, चाहे उनकी पारिवारिक आय कितनी भी हो।

इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को खेती-किसानी की जरूरतों के लिए सरकार प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सीधी नकद सहायता

YOJANASEWA.COM

<https://yojanasewa.com>

देती है। यह राशि 2,000 रुपए की तीन अलग-अलग कसितों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है।

देश के गरीब नागरिकों को खाद्य सुरक्षा देने वाली इस योजना के माध्यम से वर्तमान में भारत के लगभग 80 करोड़ लोगों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज (गेहूँ चावल) सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है।

यह योजना देश के पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों (जैसे लोहार, बढई, कुम्हार) को ट्रेनिंग और आर्थिक सहायता देने के लिए 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी। इसके तहत सरकार अब तक 41,188 करोड़ रुपए के करीब 4.7 लाख लोन स्वीकृत कर चुकी है।

15 फरवरी 2024 को शुरू हुई इस योजना के तहत घरों में सोलर पैनल लगवाने पर भारत सरकार द्वारा अधिकतम 78,000 रुपए तक की भारी सब्सिडी दी जाती है, जिससे लाभार्थियों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलता है।